



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

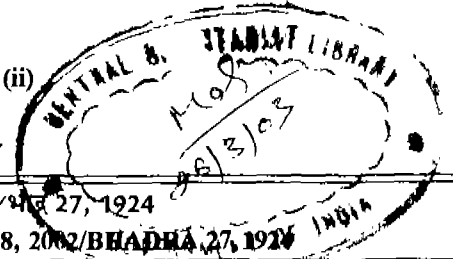
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2002/भा. 27, 1924

No. 820]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2002/BHADRA, 27, 1924



पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2002

का.आ. 1008(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्राधिकरण का गठन करती है, जो केन्द्रीय सशक्तता समिति के नाम से ज्ञात होगा, (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), जिसमें

निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 और 171/96 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 9 मई, 2002 और 9 सितम्बर, 2002 के आदेशों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का, जिनमें वन और वन्य जीव तथा उक्त आदेशों से उद्भूत विवादों से संबंधित विषय आते हैं, मानीटर करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया है :-

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | श्री पी.वी. जयकृष्णन,
(वर्तमान सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय) | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री एन.के. जोशी,
(वर्तमान अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण और वन मंत्रालय) | सदस्य |
| (iii) | श्री वाल्मीक थापर, रणथम्भौर फाउंडेशन | सदस्य |
| (iv) | श्री महेन्द्र व्यास, एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय | |

- (v) श्री एम.के.जिवराजिका, सदस्य सचिव
(वर्तमान वन महानिदेशक, पर्यावरण और वन
मंत्रालय)

2. समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :—

I. टी.एन. गोदवरमन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य तथा एनवायरमेंट अवेयरनेस फोरम बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के मामले में क्रमशः रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 और 171/96 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने तारीख 9 मई, 2002 के आदेश द्वारा समिति को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त किए गए हैं, अर्थात् :—

- (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन को मोनीटर करना और न्यायालय के समक्ष अधिक्रमण को हटाने, कार्यकारी योजनाओं, प्रतिकरात्मक वनरोपण पौधरोपण और अन्य संरक्षण विवादों के संबंध में अननुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना,
- (ii) उक्त रिट याचिकाओं (जो माननीय न्यायालय द्वारा इसे निर्दिष्ट की जाएं) में राज्यों द्वारा फाइल की गई रिपोर्टों और शपथ पत्रों की जांच करना और माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना ;
- (iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के तात्पर्य से सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध राहत प्राप्त करने के लिए या ऐसे आदेशों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति या निकाय या अभिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदनों की सुनवाई करना या माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ऐसे आवेदनों का निपटारा करना और किसी ऐसे आवेदन जिसका समुचित रूप से निपटारा किया जा सके, उसे माननीय न्यायालय को निर्दिष्ट करना ;
- (iv) समिति के पास, अपने कृत्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन समिति को प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित शक्तियां होंगी :
 - (क) किसी व्यक्ति या संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य पदाधिकारी से किन्हीं दस्तावेजों को मंगाना ;

- (ख) किसी व्यक्ति को समन करना और ऐसे व्यक्ति से या तो शपथ पत्र पर या अन्यथा साक्ष्य लेना ;
 - (ग) अपने कार्य के संबंध में उसके द्वारा अपेक्षित किन्हीं व्यक्ति(यों) या पदाधिकारी(यों) की सहायता मांगना या उन्हें उपस्थित कराना ;
 - (घ) आवेदन पत्रों और अन्य विवादों पर कार्रवाई करने के लिए अपनी प्रक्रिया विनिश्चित करना ;
 - (ङ) विशिष्ट विवादों पर कार्रवाई करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को इसके सदस्य के रूप में या विशेष आमंत्रितों के रूप में सहयोजित करना ; और
 - (च) राज्य से संबंधित विवादों पर कार्रवाई करते समय, जहां कहीं साध्य हो, उस राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को विशेष आमंत्रितों के रूप में सहयोजित करना ।
- II. निदेश जारी करने और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में ऐसे उपाय करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियां ;
- III. उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में अंतर्विष्ट उपबंधों का आश्रय लेने की शक्तियां ;
- IV. अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन शक्तियां ;
- V. आरा मिलों और अन्य काष्ठ आधारित उद्योगों की अवस्थिति, कार्यकरण और मानीटरी तथा संपोषणता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी संख्यांक और क्षमता को विनियमित करने के संबंध में दिशा-निर्देश और या निदेश जारी करने की शक्तियां ;
- VI. वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंध के संबंध में, जिनके अंतर्गत वनोन्मूलन अधिक्रमण, कार्य योजनाओं, प्रतिकरात्मक वनरोपण, पोधरोपण, पुररुद्धार, अवैध

कटाई, इमारती लकड़ी और इमारती लकड़ी उत्पादों तथा अन्य वनोत्पाद का परिवहन, वन क्षेत्र में खनन, गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का अवैध अपयोजन तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मामले भी हैं, कृत्य और शक्तियां ;

VII. माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समिति को निर्दिष्ट किसी विवाद्यक की जांच करने और कार्रवाई करने की शक्तियां ।

3. समिति के सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में नियुक्त किया जाता है और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं हटाया जाएगा ।
4. समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यक्षीय, केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में पर्यावरण और वन मंत्रालय में कृत्य करेगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा ।
5. पर्यावरण और वन मंत्रालय, समिति को उपयुक्त और पर्याप्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा । समिति के कार्यकरण पर उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत सदस्यों और सहायक कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक भी हैं, (सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने की सीमा तक) की पूर्ति विशेष अन्वेषण दल (वि०अं०टी०) द्वारा प्रोद्भूत आय में से की जाएगी । समिति इसके लिए आवश्यक कार्य प्रक्रिया समिति द्वारा विशेष अन्वेषण दल से परामर्श करके तैयार करेगी ।
6. समिति की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।
7. समिति, तिमाही रिपोर्टें, माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी । इसको यह स्वतंत्रता होगी कि जब आवश्यक हो तब यह माननीय न्यायालय से स्पष्टीकरण या उपांतरण प्राप्त करे ।

[सं. 13-21/98-एसयू-पार्ट II]

आर. चन्द्र मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2002

S.O. 1008(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Central Empowered Committee, (hereinafter referred to as the Committee), consisting of the following members appointed in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated the 9th May, 2002 and 9th September 2002 in Writ Petitions (Civil) No. 202/95 and 171/96, for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the purposes of monitoring and ensuring compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court covering the subject matter of forests and wildlife, and related issues arising out of the said orders:-

- | | | |
|-------|--|------------------|
| (i) | Shri P.V.Jayakrishnan,
[presently Secretary to the Government of
India, Ministry of Environment and Forests] | Chairman |
| (ii) | Shri N.K.Joshi,
[presently Additional Director General of
Forests, Ministry of Environment and
Forests] | Member |
| (iii) | Shri Valmik Thapar, Ranthambore
Foundation | Member |
| (iv) | Shri Mahendra Vyas, Advocate, Supreme
Court of India | Member |
| (v) | Shri M.K. Jiwrajka,
[presently Inspector General of Forests,
Ministry of Environment and Forests] | Member Secretary |

2. The Committee shall exercise the following powers and perform the following functions :-

- I. Powers and functions conferred upon the Committee by the Hon'ble Supreme Court of India by its order dated the 9th May, 2002, in Writ

Petitions (Civil) No. 202/95 and 171/96 in the case of T. N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India and others and Environment Awareness Forum Vs. State of J and K and others, respectively, namely :-

- (i) to monitor the implementation of the Hon'ble Court's orders and place reports of non-compliance before the Court including in respect of encroachments removals, working plans, compensatory afforestation, plantations and other conservation issues;
- (ii) to examine pending interlocutory applications in the said writ petitions (as may be referred to it by the Hon'ble Court) as well as the reports and affidavits filed by the States in response to the orders passed by the Hon'ble Court and place its recommendations before the Hon'ble Court for orders;
- (iii) to hear applications filed by any aggrieved person seeking relief against any action taken by the Government or any other authority purportedly in compliance of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court or against any action of any person or body or agency in violation of such orders, and to dispose of such applications in conformity with the orders of the Hon'ble Court and to refer to the Hon'ble Court any application which cannot be appropriately disposed off ;
- (iv) without prejudice to the generality of the powers conferred upon the Committee under the provisions of the said Act, for the purposes of effective discharge of its functions, the Committee shall have the powers to:
 - (a) call for any documents from any person or the government of the Union or the State or any other official;

- (b) summon any person and receive evidence from such person on oath either on affidavit or otherwise;
 - (c) seek assistance or presence of any persons(s) or official(s) required by it in relation to its work;
 - (d) decide its own procedure for dealing with applications and other issues;
 - (e) co-opt one or more persons as its members or as special invitees for dealing with specific issues; and
 - (f) co-opt, wherever feasible, the Chief Secretary and Principal Chief Conservator of Forests of the State as special invitees while dealing with issues pertaining to that State.
- II. Powers under section 5 of the said Act, for issuing directions and taking such measures in respect of any of matters referred to in sub-section (2) of section 3 of the said Act;
- III. Powers to take resort to the provisions contained in sections 15 to 21 of the said Act;
- IV. Powers under section 4 of the said Act, for appointment of officers.
- V. Powers to issue guidelines and or directions with regard to location, functioning and monitoring of the saw mills and other wood based industries and also regulate their numbers and capacity for ensuring sustainability;
- VI. Functions and powers in respect of protection and management of forests and wildlife including in respect of deforestation, encroachments, working plans, compensatory afforestation, plantations, regeneration, illegal felling,

transportation of timber and timber products and other forest produce, mining in forest area, illegal diversion of forest lands for non-forest purpose and other matters relating to the implementation of the Forest (Conservation) Act, 1980, Indian Forest Act, 1927, Wildlife (Protection) Act, 1972 and the rules, regulations and guidelines framed thereunder;

VII. Powers to examine and deal with any issue referred to the Committee by the Hon'ble Supreme Court or the Central Government.

3. The members of the Committee are appointed in their personal capacity and shall not be removed without leave of the Hon'ble Supreme Court.

4. Subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court, the Committee shall function under the administrative control of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests with headquarters at Delhi.

5. The Ministry of Environment and Forests shall provide suitable and adequate office accommodation for the Committee. The expenditure incurred on the working of the Committee including salary or remuneration to the members and supporting staff, (to the extent not payable by the Government) may be met out of income accruing to the Special Investigation Team (SIT). Necessary procedure for this may be formulated by the Committee in consultation with the Special Investigation Team.

6. The jurisdiction of the Committee shall extend to the whole of India.

7. The Committee shall submit quarterly reports to the Hon'ble Supreme Court. It will be liberty to seek clarifications or modifications needed by it from the Hon'ble Court.

[No. 13-21/98-SU-PT. II]

R. CHANDRA MOHAN, Jt. Secy.